

• बजट...

## रेलवे विस्तारीकरण के लिए 2698 करोड़

राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के भेंट की इस अवसर पर राज्यसभा सांसद की केंद्रीय मंत्री से हिमाचल प्रदेश को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने केंद्र सरकार का धन्यवाद किया कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखा है यह बहुत बड़ी बात है। महाजन ने कहा कि हिमाचल को बजट में विशेष स्थान मिला है, जिसमें वित्त मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के आपादा को लेकर विशेष मदद का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि इस बार के रेल बजट में भी हिमाचल को रिकॉर्ड बजट प्राप्त हुआ है, वर्ष 2024-25 के बजट में हिमाचल के लिए 2698 करोड़ रुपये रेलवे विस्तारीकरण सहित अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवंटित किए हैं। हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास के लिए जारी बजट पूर्व की यूपीए सरकार से 25 गुणा ज्यादा है। यह हिमाचल में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल में नैरोगेज को छोड़कर रेलवे ने 100 प्रतिशत बिजलीकरण का काम पूरा कर लिया है। राज्य में शिमला सहित चार स्टेशनों को

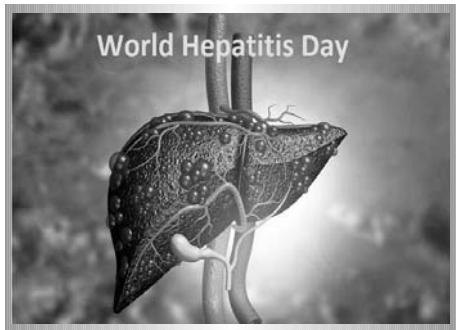


विश्वस्तरीय मानकों के आधार पर निर्मित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में चार रेलवे स्टेशन को बर्लैड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाए। इनमें अंब-अंदौरा, बैजनाथ पपरोला, पालमपुर, शिमला को शामिल किया गया है। भानुपली बिलासपुर-बैरी, चंडीगढ़-बद्दी और नंगल हैम-तलवाड़ी रेललाइन का कार्य तेज गति से चल रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति काफी अलग है इसके लिए हिमालय टनलिंग मैथड के तहत कार्य किया जाएगा। चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इसमें पहले अंतरिम बजट में भी इसकी घोषणा हुई थी। अंबाला मंडल के डीआरएम मंदीप सिंह भाटिया ने बताया कि रेलवे ने वर्ष 2007 में इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। यह रेललाइन 33.23 किलोमीटर लंबी है। नंगल हैम-तलवाड़ी रेल लाइन के लिए 500 करोड़ रुपये और भानुपली-बिलासपुर-बैरी रेललाइन के 1700 करोड़ का बजट जारी किया है।

■ अनल पत्रवाल  
संपादक, हिमाचल अभी अभी

• संपादकीय...

## विश्व हेपेटाइटिस दिवस



हेपेटाइटिस लिवर में होने वाली सूजन है, जो वायरस, शराब के सेवन, विषाक पदार्थों या कृषि दवाओं सहित विभिन्न कारकों के कारण हो सकती है। हेपेटाइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे आम वायरल हेपेटाइटिस है, जो एक विशेष वायरस के कारण होता है। लिवर हमारे शरीर का एक अहम अंग है। यह शरीर से टॉक्सिस्ट बाहर निकालने के साथ ही कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करता है। हेपेटाइटिस लिवर से जुड़ी एक गंभीर समस्या है, जिससे लेकर जागरूकता फैलाने के मक्सद से हर साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल 28 जुलाई को नेबेल-पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉ. बारूक ब्लमर्ग के जन्मदिवस के मौके पर मनाया जाता है। डॉ. बारूक ने ही हेपेटाइटिस बी वायरस (एचबीवी) की खोज की थी और इस वायरस के लिए एक परीक्षण और टीका विकसित किया था। हेपेटाइटिस में पांच तरह के संक्रमण होते हैं, 'ए', 'बी', 'सी', 'डी' और 'ई'। हेपेटाइटिस का खतरा कई कारणों से हो सकता है, जैसे कमज़ोरी इम्यूनिटी, खानपान में गड़बड़ी, ड्रग्स, शराब और नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करने से इस बीमारी का खतरा ज्यादा हो सकता है। मानसून के दौरान, जल प्रदूषण एक आम समस्या होती है, जो हेपेटाइटिस का कारण बन सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए हमेशा ऊबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। घर में वॉटर प्यूरीफायर का इस्टेमाल करें और कहीं से भी पानी पीने से बचें। इसके अलावा यात्रा करते समय अपनी पानी की बोतल साथ रखें। प्रदूषण की संभावना बढ़ने के कारण मानसून के दौरान स्ट्रीट फूड और कच्चे फूड आइटम्स को खाना विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए ताजा और पका हुआ भोजन चुनें। हेपेटाइटिस को फैलने से रोकने के लिए किसी भी तरह के वेस्ट प्रोडक्ट खासकर ह्यूमन वेस्ट को सही तरीके डिस्पोज करें। कृषि प्रकार के हेपेटाइटिस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन एक बेहद प्रभावी तरीका है। हेपेटाइटिस ए और बी की वैक्सीन लगावाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें, खासकर आगर आप हाई रिस्क में हैं या इस बीमारी के फैलने की संभावना वाले क्षेत्रों में रह रहे हैं।

■ अनल पत्रवाल

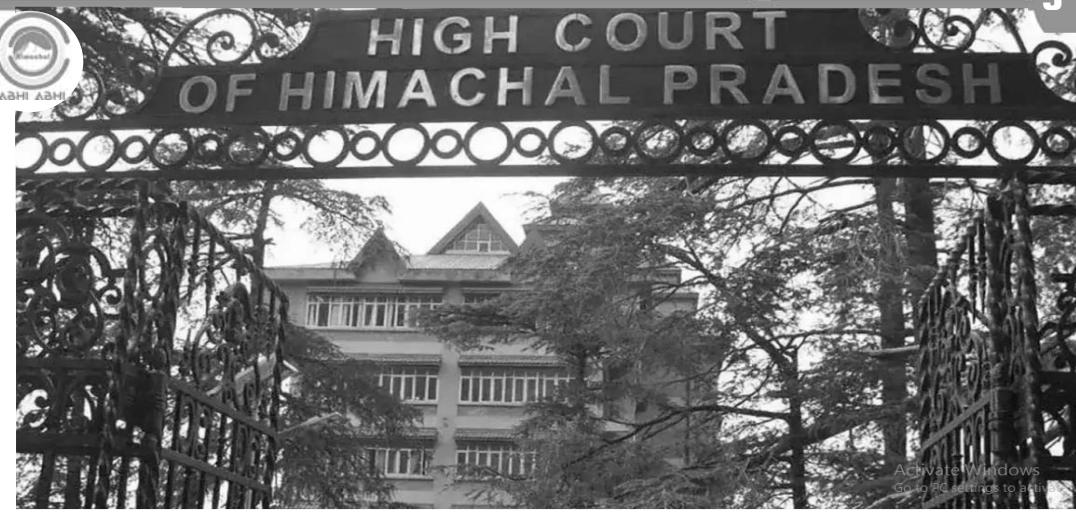
संपादक, हिमाचल अभी अभी

• उपलब्धि...

## सिरमौर को पुरस्कार



नाहन : चौधरी सरबन कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) के कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर स्थित धौलाकुआं को प्राकृतिक खेती पर कार्य करने के लिए 'उत्कृष्ट प्राकृतिक खेती पुरस्कार' शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय श्रीनगर में प्रदान किया गया। ये पुरस्कार कवीके सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने प्राप्त किया। डॉ. पंकज मित्तल ने बताया कि 22-23 जुलाई को शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय शालीमार-कश्मीर में कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्राकृतिक खेती के उत्तरान पर प्रगति समीक्षा व जागरूकता कार्यशाला के दौरान सिरमौर को प्राकृतिक खेती पर कार्य करने के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। श्रीनगर में आयोजित की गई कार्यशाला में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रमुख डॉ. पंकज मित्तल और डॉ. शिवाली धीमान को श्रीनगर में कार्यशाला के समाप्त समारोह के दौरान ये पुरस्कार प्रदान किया।



संबंधित  
अधिकारियों को  
यह भी निर्देश  
दिया गया है कि

वह अगर उक्त  
भूमि के  
सीमांकन के  
दौरान अन्य  
अतिक्रमणों  
को मोके पर  
पाते हैं तो  
उन्हें भी  
समयबद्ध तरीके  
से वन भूमि से  
कानून के दायर  
में रहकर उचित  
कार्रवाई करके  
छह माह में हटा  
दें।

कब्जाई वन भूमि  
पर यदि कोई  
निर्माण किया  
गया है तो वह  
हिमाचल प्रदेश सरकार या वन  
विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी है कि यदि वह निर्माण से जुड़ी सामग्री उक्त वन भूमि से खुद ही हटाकर ले जाना चाहे तो वह 30 अक्टूबर, 2024 से पहले यह कार्य कर सकता है। संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के सीमांकन के दौरान अन्य अतिक्रमणों को मोके पर पाते हैं तो उन्हें भी समयबद्ध तरीके से वन भूमि से कानून के दायर में रहकर उचित कार्रवाई करके छह माह में हटा दें। कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी है कि यदि वह निर्माण से जुड़ी सामग्री उक्त वन भूमि से खुद ही हटाकर ले जाना चाहे तो वह 30 अक्टूबर, 2024 से पहले यह कार्य कर सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों की

अनुपालना में किसी भी लापरवाही या ढिलाई को

निहित हो गयी है।

विभिन्न कानूनों के अनुसार वन भूमि के

संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश

दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के

सीमांकन के दौरान अन्य

अतिक्रमणों को मोके पर

पाते हैं तो उन्हें भी समयबद्ध

तरीके से वन भूमि से

कानून के दायर

में रहकर उचित

कार्रवाई करके छह माह में हटा

दें। कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी है कि यदि वह निर्माण से जुड़ी सामग्री उक्त वन भूमि से खुद ही हटाकर ले जाना चाहे तो वह 30 अक्टूबर, 2024 से पहले यह कार्य कर सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों की

अनुपालना में किसी भी लापरवाही या ढिलाई को

निहित हो गयी है।

विभिन्न कानूनों के अनुसार वन भूमि के

संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश

दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के

सीमांकन के दौरान अन्य

अतिक्रमणों को मोके पर

पाते हैं तो उन्हें भी समयबद्ध

तरीके से वन भूमि से

कानून के दायर

में रहकर उचित

कार्रवाई करके छह माह में हटा

दें। कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी है कि यदि वह निर्माण से जुड़ी सामग्री उक्त वन भूमि से खुद ही हटाकर ले जाना चाहे तो वह 30 अक्टूबर, 2024 से पहले यह कार्य कर सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों की

अनुपालना में किसी भी लापरवाही या ढिलाई को

निहित हो गयी है।

विभिन्न कानूनों के अनुसार वन भूमि के

संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश

दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के

सीमांकन के दौरान अन्य

अतिक्रमणों को मोके पर

पाते हैं तो उन्हें भी समयबद्ध

तरीके से वन भूमि से

कानून के दायर

में रहकर उचित

कार्रवाई करके छह माह में हटा

दें। कब्जाई वन भूमि पर यदि कोई निर्माण किया गया है तो वह हिमाचल प्रदेश सरकार या वन विभाग द्वारा उपयोग किया जाएगा। कोर्ट ने प्रार्थी को छूट दी है कि यदि वह निर्माण से जुड़ी सामग्री उक्त वन भूमि से खुद ही हटाकर ले जाना चाहे तो वह 30 अक्टूबर, 2024 से पहले यह कार्य कर सकता है।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उपरोक्त निर्देशों की

अनुपालना में किसी भी लापरवाही या ढिलाई को

निहित हो गयी है।

विभिन्न कानूनों के अनुसार वन भूमि के

संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश

दिया गया है कि वह अगर उक्त भूमि के

सीमांकन के दौरान अन्य